made a cognisable offence under the Electricity Supply Act, 1948. The package of measures for improving the efficiency of Boards include, interalia, implementation of centrally sponsored renovation and modernisation schemes, introduction of incentive schemes for improving performance of thermal power stations, reducing transmission and distribution losses etc.

(c) Every effort is made by the State Electricity Boards to supply electricity to the farmers at reasonable rates and for sufficient number of hours in a day.

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं का निजीकरण

156. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को कुछ विद्युत परियोजनाओं के निजीकरण किए जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजे है;

(ख) यदि हां, तो उन विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इस सम्बन्ध में स्वीकृति दे दी है;

(घ) इन परियोजनाओं के निजीकरण किए जाने के पीछे क्या तर्क है;

(ङ) क्या भारत सरकार की इस सम्बन्ध में सहमति है; और

(च) क्या निजी कम्पनियों ने निजीकरण के बाद इन परियोजनाओं में काम करने वाले लोगों की छंटनी न किए जाने का आश्वासन दिया है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) जी, हां।

(ख) विष्णुप्रयाग जल विद्युत शक्ति परियोजना (400 मे०वा०) एक मात्र ऐसी परियोजना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) परियोजना का सम्पूर्ण वित्तपोषण, निजी क्षेत्र से होगा।

(ङ) जी हां।

(च) उ० प्र० राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि विष्णुप्रयाग जल विद्युत शक्ति परियोजना में कार्यरत लोगों को, यू०पी०एस०ई०बी० के अन्य स्थल/परियोजनाओं और सिंचाई विभाग में स्थानांतरित किया जायेगा।

आनपारा ताप विद्युत परियोजना के लिए केन्द्रीय सहायता

157. **श्री आनन्द प्रकाश गौतम:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को, आनपारा ताप विद्युत परियोजना के लिए वर्ष 1993-94 के परिव्यय के आधे अंशदान के रूप में निर्धारित धन-राशि का भुगतान कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं तो, उसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश सरकार को देय धनराशि कितनी है; और

(घ) उसका भुगतान भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को किस रूप में करती रही है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) राज्य परियोजना के रूप में, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा स्थापित की जाने वाली, ओ०ई०सी०एफ० (जापान) से सहायता प्राप्त अनपारा "बी" ताप विद्युत परियोजना (2×500 मे०वा०) के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को रुपये के रूप में संसाधनों को जुटाया जाना है।

(ख) से (घ) तथापि भारत सरकार ने वर्ष 1991-92 के दौरान, उत्तर प्रदेश सरकार के लिये 127 करोड़ रुपये की एक विशेष ऋण सहायता स्वीकृत की थी, ताकि उ०प्र० राज्य बिजली बोर्ड द्वारा अनपारा "बी" परियोजना के लिये आवांतित उपस्करों से संबंधित सीमा शुल्क दायित्वों को पूरा किया जा सके। चालू वर्ष में इस प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की गई है।

बिहार में विद्युत उत्पादन और खपत

158. **श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में कुल कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है;

(ख) बिहार में कुल कितनी विद्युत की खपत की

मांग है;

(ग) क्या सरकार उस मांग को पूरा करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार कुल विद्युत उत्पादन में से बिहार को उसके खपत एवं मांग के अनुपात में बिजली आपूर्ति करने का विचार रखती है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०वी० रंगैया नायडू): (क) से (घ) बिहार राज्य बिजली बोर्ड से संबंधित अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

विद्युत उत्पादन संकल	(मि०यू०)	आवश्यकता आंकड़े	उपलब्धता मि०यू० में)	अवधि: अप्रैल-दिसम्बर, 1993 कमी	प्रतिशत कमी
लक्ष्य 2789	वास्तविक 2204	6365	4249	2116	33.2

राज्य में विद्युत आपूर्ति की जिम्मेवारी संबंधित राज्य/राज्य विद्युत बोर्ड की है। केन्द्रीय सरकार अपनी विद्युत उत्पादन यूनिटों से राज्य को उसका हिस्सा देती है तथा इसके साथ-साथ अनावंटित कोटे से तथा अन्य क्षेत्रों से उन राज्यों को बिजली की कमी को पूरा करने में सहायता प्रदान करती है जो केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत हेतु भुगतान करने में सक्षम हैं।

Maharashtra Government's proposals for Power Sector

159. SHRIMATI CHANDRIKA ABHINANDAN JAIN: Will the Minuter of POWER be pleased to state:

(a) the number of proposals for new power projects that have been submitted so far by the Maharashtra Government to the Union Government for approval during 1992-93;

(b) the present status of the said projects;

(c) whether it is a fact that Government have taken measures for the clearance of the pending proposals during the current financial year;

(d) if so, the details thereof; project wise, indicating the amount to be released; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P.V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (c) The status of the power projects referred by Govt. of Maharashtra to Central Electricity Authority (CEA) for accord of techno-economic clearance during the year 1992-93 and 1993-94 (uptill January, 1994) is given below:—

S.No.	Name of Project	Date of ke ceipt	Status
1 .	Cbiluddhan Pumped Storage Scheme (4X100 MW)	3/93	The scheme has been referred by the State Govt, to Central Electricity Authority for techno-economic clearance. The State Govt, of Maharashtra had referred these proposals to Central Electricity Authority for techno-economic clearance for executing the projects in the private sector. Dabhol project has been cleared by the CEA subject to certain conditions. The Khaperkheda Project has been accorded 'in principle clearance' of CEA subject to certain conditions.
2	Barge Mounted Power plant (110 MW) near Dabhol	9/92 4/93	
2.	Dabhol CCCT (2015 MW) Khaperkheda	7/93	
3.	(2x210MW) Units 5 46		